आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 22.03.2025
समय 07.20

मुख्य समाचार :—

- प्रदेश के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश।
- मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भूकंप संवेदनशील राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का उपयोग करने पर जोर दिया।
- केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा — सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रत्येक किसान को डिजिटल पहचान पत्र मिलेगा।
- और, वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बैंकों से आम नागरिकों को सरल, सुरक्षित और प्रभावी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध्‍ा कराने के निर्देश दिये।

हीट वेव बचाव

प्रदेश के सभी जिलों में आपदा प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिये गये हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिला आपदा प्रबंधन योजना और राज्य आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये।

वहीं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आगामी गर्मी के मौसम के लिए राज्यों के साथ बैठक कर हीट वेव से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, इस साल तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। बैठक के दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, एन०डी०एम०ए ने अस्पतालों में हीट स्ट्रोक रूम बनाने, और एंबुलेंस में हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। एन०डी०एम०ए मुख्यालय से हुई इस बैठक में सभी राज्यों को हीट वेव कार्ययोजना बनाने और प्रत्येक राज्य में एक हीट नोडल अधिकारी की तैनाती करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भूकंप संवेदनशील राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की निर्माण सामग्री का उपयोग करने और बिल्डिंग कोड का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। देहरादून में आयोजित आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में मुख्य सचिव ने सभी कार्यदायी एजेंसियों को बिल्डिंग कोड से संबंधित कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने राज्य में हाल ही में घटित हिमस्खलन जैसी आपदाओं की केस स्टडी तैयार करने का निर्देश दिया और आपदा संवेदी क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक स्पष्ट एसओपी बनाने को कहा। उन्होंने स्थानीय समुदायों को हिमस्खलन जैसी आपदाओं से बचाव और राहत के लिए जागरूक करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में नेशनल ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम और राष्ट्रीय भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम पर भी चर्चा की गई।

<u>इण्डो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला</u>

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित इण्डो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला और पर्यटन महोत्सव में भाग लिया। इस दौरान, उन्होंने भारत और नेपाल के स्थानीय उत्पादों पर आधारित स्टालों का दौरा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह महोत्सव भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक संबंधों को मजबूत करेगा। उन्होंने भारत और नेपाल के बीच सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों की बात की। उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल की जनता की आस्था अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में दिखाई दी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्तों के और मजबूत होने की बात की। उन्होंने बताया कि नेपाल और भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और उत्तराखंड से नेपाल तक कई पर्यटन और धार्मिक स्थल हैं। श्री धामी ने जोर देते हुये कहा कि उत्तराखंड सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार को सुगम बनाने के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। उन्होंने काली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बांध परियोजना का उल्लेख भी किया, जो दोनों देशों के लिए साझा ऊर्जा उत्पादन का अवसर प्रदान करेगा।

<u>पुरस्कार</u>

राज्य सरकार ने नैक एक्रीडेटेड और एन०आई०आर०एफ रैंकिंग प्राप्त राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 5 से 10 लाख रुपये तक की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। यह निर्णय उच्च शिक्षा

मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के अनुमोदन के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है।

नैक ग्रेड के आधार पर ग्रेड 'बी' को 5 लाख, 'बी प्लस' को 6 लाख, 'बी प्लस–प्लस' को 7 लाख रुपए दिये जांएगे, जबकि 'ए' ग्रेड मिलने पर 8 लाख, 'ए प्लस मिलने पर 9 लाख और 'ए प्लस–पल्स' ग्रेडिंग मिलने पर दस लाख रुपए की धनराशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। एन०आई०आर०एफ में शीर्ष दो सौ में आने वाले संस्थान और 675 से अधिक अंक प्राप्त एनबीए रैंकिंग वाले संस्थानों को भी 10 लाख रुपये मिलेंगे।

शास्त्रोत्सव

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में आयोजित 62वे अखिल भारतीय शास्त्रोत्सव के समापन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्र केवल ग्रंथ नहीं, बल्कि सृष्टि के रहस्यों को जानने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। वेद, उपनिषद, और पुराणों में जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पहलुओं का संतुलन बताया गया है, जो इसे अन्य ज्ञान परंपराओं से श्रेष्ठ बनाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय गणितज्ञों ने शून्य और दशमलव जैसी अवधारणाएं विकसित की, जिन पर आज का आधुनिक विज्ञान टिका हुआ है। उन्होंने युवा पीढ़ी को इन अद्वितीय अवधारणाओं से अवगत कराने के महत्व पर जोर देते हुए शास्त्रोत्सव जैसे आयोजनों को इस दिशा में महत्वपूर्ण बताया।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से प्राचीन संस्कृति और ज्ञान को संरक्षित करने के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने विद्वानजनों से अनुरोध किया कि वे वेदों और उपनिषदों को सरलता से समझाने के तरीके पर विचार करें, ताकि आने वाली पीढ़ी इन्हें समझ सके।

लोकसभा चर्चा

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में वर्ष 2025–26 के लिए के लिए कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले दस वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में दस लाख करोड़ रुपये से अधिक का आवंटन किया है। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने अब तक 75 करोड़ 74 लाख मीट्रिक टन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की है। कृषि मंत्री ने कहा कि डिजिटल एग्री मिशन के अंतर्गत देश के हर किसान को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसान विभिन्न सरकारी

योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुकसान से व्यापक सुरक्षा प्रदान करती है।

बैंकिग सुविधांए

वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे आम नागरिकों को सरल, सुरक्षित और प्रभावी डिजिटल बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराएं। सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कम नकदी जमा अनुपात प्रदर्शित करने वाले बैंकों की प्रभावित निगरानी के लिये योजना बढ़ाने और इसमें आवश्यक सुधार लाने को कहा।

श्री जावलकर ने दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी को बैंकिंग सेवाओं में रुकावट का कारण न बनने देने पर जोर दिया। उन्होंने बैंकिंग मित्रों से लोगों की छोटी समस्याओं का समाधान करने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के निर्देश दिये।

वित्त सचिव ने कॉर्पोरेट बैंकों को सरकारी और कोऑपरेटिव बैंकों की तरह आम जनता को डिजिटल साक्षरता के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकिंग सेवाओं से छूटे गांवों को आच्छादित करने के लिए यूपीसीएल, बीएसएनएल और उरेडा के साथ बैठक कर समाधान निकालने को कहा।

मंजूरी

केंद्र सरकार ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की पहल को स्वीकार करते हुए कोटद्वार और गोपेश्वर में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से इन क्षेत्रों के निवासियों को पासपोर्ट सेवाएं सुलभ रूप से मिल सकेंगी। सांसद बलूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस. जयशंकर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस कदम से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें पासपोर्ट संबंधी प्रक्रियाओं में कोई कठिनाई नहीं होगी।

केदारनाथ यात्रा तैयारी

इस वर्ष 2 मई से शुरू होने वाली विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि यात्रा मार्ग पर सड़कें खराब या क्षतिग्रस्त न रहें। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सड़क मरम्मत का काम अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक पूरा कर लिया जाए। नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों को यात्रा मार्ग, पड़ाव स्थलों, बाजारों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सफाई व्यवस्था चाक–चौबंद रखने के निर्देश दिए गए।

सभी व्यवस्थाओं को 20 अप्रैल तक पूरा करने की बात कहते हुए, जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को केदारनाथ यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने यात्रा मार्ग में पर्याप्त संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती और डॉक्टरों की टीम की उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा।

और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर––

आज सभी समाचार पत्रों ने अलग–अलग सुर्खियों को प्राथमिकता दी है।

ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से उत्तराखंड में सोना–चांदी की तलाश होगी। इस शीर्षक के साथ अमर उजाला लिखता है– भूत्तव एवं खनिकर्म विभाग के अंतर्गत अलग से बनेगा निदेशालय, आस्ट्रेलिया का मोनाश विश्वविद्यालय, आईआईटी रूड़की व सरकार के बीच होगा एमओयू।

कोटद्वार और गोपेश्वर में जल्द ही पासपोर्ट ऑफिस खोले जांएगे। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की सोशल मीडिया पोस्ट पर दी गई इस जानकारी को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है।

शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार–2024 के लिए शिक्षकों के चयन की ख़बर पर हिंदुस्तान समाचार पत्र लिखता है– उत्तराखंड के 16 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी पुरस्कार।

प्रदेश की भाजपा सरकार अपने इस कार्यकाल का तीसरा वर्ष पूरा कर रही है। इस ख़बर पर दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हवाले से लिखता है– जिला व विधानसभा क्षेत्र स्तर पर लगेंगे बहुद्देशीय शिविर।